SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA (Orissa): Sir, I associate myself with it.

Non-payment of dues to sugarcane farmers in U.P

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (हरियाणा) : माननीय सभापति जी, मैं देश भर के गन्ना किसानों को उनके गन्ने के मूल्य का भुगतान न किए जाने के संबंध में आपकी अनुमति से विशेष उल्लेख के माध्यम से यह बिंदु उठा रहा हूं। मान्यवर, आज पूरे देश का गन्ना उत्पादक बरबादी के कगार पर खड़ा है उसका गन्ना जो चीनी मिल मालिक खरीदतें हैं, उसका भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है और यही नहीं, जो केन्द्र सरकार की गन्ना क्रय अधिनियम के तहत 14 प्रतिशत ब्याज देने की व्यवस्था है, उसका भी अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। किसान को एक **पैसे की भुगतान नहीं किया है। अतः आप से अनुरोध है कि आप इस अदिलम्बनीय लोक महत्व के प्रशन** तरफ उसके गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा है जिसके कारण वह भुखमरी के कगार पर खड़ा है।

श्री सभापति :आप पढ़कर बोलिए, आप जबानी बोल रहे हैं। पढ़कर बोलिए, यहां स्पेशल मेंशन में पढ़कर बोला जाता है।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक : मान्यवर, गन्ना किसान को सहकारी और सरकारी देय की वसूली में जेल भेजा जा रहा है। उनकी अगली फसलों की बिजाई नहीं हो पा रही है। सरकार को इसमें तत्काल हस्तक्षेप कर किसानों को उनके गन्ना मूल्य का ब्याज सहित भुगतान कराने की व्यवस्था करानी चाहिए। यह एक अत्यंत लोक महत्व का प्रश्न है। इसकी अनेदेखी करने से किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानका गन्ना मूल्य के भुगतान के संबंध में बहुत बुरा हाल है। कुछ चीनी मिलों ने 31 दिसम्बर के बाद से एक प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कृपा करें।

Need to purchase unsold tobacco in Andhra Pradesh by State Trading Corporation

SHRI YADLAPATI VENKAT RAO (Andhra Pradesh): Mr. Chairman, Sir, my Special Mention is related to the purchase of unsold tobacco in Andhra Pradesh by the State Trading Corporation.

Sir, tobacco is a commercial crop grown in a large area in Andhra Pradesh, providing employment to millions of people; it is also a good foreign exchange earner. During the 2001-02 crop season, the Tobacco Board had planned a crop size of 101.45 million kgs. in Andhra Pradesh, and the overall production is currently estimated at 113.47 million kgs. Until now, "the farmers could dispose of only 32 million kgs. and the balance 82 million kgs. are lying with the farmers for want of buyers. There is also the